श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का बयान

कल प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई बीमा योजनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के साथ कल देशभर में काफी धूमधाम के साथ अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लॉन्च किया। श्री मोदी ने कहा, कि वह 'राजनीतिक फायदे' के लिए इन योजनाओं का लॉन्च नहीं कर रहे हैं और वे उन अल्पकालिक राजनीतिज्ञों में नहीं हैं, जो केवल अगला चुनाव जीतने के लिए कुछ योजनाओं का लॉन्च करते हैं।

हालांकि जिस चतुराई और धोखे से पुरानी योजनाओं को रिपैकेज़ कर पुनः लॉन्च किया गया है, वे प्रधानमंत्री के दावों को खारिज करती हैं। सच्चाई यह है, कि कल मीडिया की हाई वोल्टेज़ गतिविधिओं के बीच एक बार फिर सरकार के ईवेंट मैनेज़मेंट स्टाईल में नाम बदलने, पैकेजिंग बदलने और रिलॉन्च करने का जबरदस्त प्रयास किया गया। इसने सरकार के काम करने के नमो स्टाईल अर्थात् 'नथिंग ओरिज़नल के संदेश को फिर से दोहराया है।

दावे के विपरीत कल मोदी सरकार द्वारा की गई पूरी गतिविधि का लक्ष्य सिर्फ श्रेय लेना, लोगों के प्रति सहृदय दिखना और जनविरोधी सरकार की सूट बूट वाली छवि को बदलना था, जो इस सरकार ने अपने जनविरोधी निर्णयों से, पूंजीपति समर्थकों के पक्ष में लिए गए फैसलों की बदौलत बनाई है।

देश के लोग इस छलावे को समझते हैं। वे जानते हैं, कि ये योजनाएं कुछ नहीं, बल्कि नए पैकेज़ में आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना हैं, जो पिछली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए लॉन्च की थीं।

इन सूदूरगामी योजनाओं ने 2007 और 2008 में अपने लॉन्च के बाद लगभग 5 करोड़ (एएबीवाई), 42 लाख (आरजीएसएसबीवाई) और 12 करोड़ (आरएसबीवाई) लोगों को लाभान्वित किया और क्रमशः 2155 करोड़ रु., 327.71 करोड़ रु. और 4300.07 करोड़ रु. यूपीए के कार्यकाल में इन योजनाओं के तहत लोगों को दिए गए थे। इन योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तियों की संचयी संख्या 17 करोड़ (6 करोड़ परिवारों) से अधिक है और इस मद में खर्च की गई कुल रकम 7800 करोड़ रु. से अधिक है।

आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) में 200 रु. प्रतिवर्ष का प्रीमियम तय है और इस रकम का 50 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा फंड से दिया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन घरों और विशेष रोजगार वाले समूहों को 100 प्रतिशत प्रीमियम का अनुदान दिया जाता है। इस योजना में 75000 रु. का दुर्घटना/स्थायी विकलांगता कवर और 30,000 रु. का प्राकृतिक मृत्यु कवर तय है। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ बीमा योजना (आरजीएसएसबीवाई) में प्रतिवर्ष 897 रु. का प्रीमियम देय है, जिसमें सामान्य श्रेणी के द्वारा केवल 200 रु. प्रतिवर्ष का प्रीमियम दिया जाता है और एससी/एसटी/बीपीएल के द्वारा 100 रु. प्रतिवर्ष का प्रीमियम दिया जाता है, बाकी का प्रीमियम भारत सरकार देती है। इस योजना में 1 लाख रु. का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर, 1 लाख रु. का प्राकृतिक मृत्यु कवर, 1 लाख रु. का आंशिक शरीरिक विकलांगता कवर और 1 लाख रु. का मेडीक्लेम कवर तय है। तीसरी योजना राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना 25 राज्यों में लागू की जा चुकी है, जिसमें लगभग सभी बीपीएल घर शामिल हैं। आरएसबीवाई के अंतर्गत

हितभागियों के परिवार के अधिकांश 5 सदस्यों अर्थात् घर के मुखिया, जीवनसाथी और तीन आश्रितों को अधिकांश बीमारियों के लिए 30000 रु. तक का ऑटोमैटिक हॉस्पिटलाइज़ेशन कवरेज़ दिया जाता है। हितभागियों को इसके लिए 30 रु. का पंजीयन शुल्क भरना होता है, जबकि बीमा कंपनी को पूरा शुल्क केंद्र और राज्य सरकार अदा करती हैं।

हमें उम्मीद है, कि मोदी सरकार देश के 17 करोड़ लोगों को सुरक्षा प्रदान करने वाली इन प्रमुख योजनाओं को बंद करना नहीं चाहेगी।

सही परिप्रेक्ष्य में 'लॉन्च' की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी यह उम्मीद करती है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार मीडिया कवरेज़ और श्रेय लेने वाली लॉन्च ईवेंट्स से आगे बढ़कर सार्थक काम करेंगे और इन फायदों को लोगों तक पहुंचाएंगे।